

संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले सीमान्त समुदायों के लिए आजीविका विकल्प के विकास की दिशा में एकीकृत दृष्टिकोण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा दिनांक 20 से 22 नवम्बर 2017 तक "संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले सीमान्त समुदायों के लिए आजीविका विकल्प के विकास की दिशा में एकीकृत दृष्टिकोण" विषय पर हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्य-जीव विंग की वित्तीय सहायता से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के पंथाघाटी स्थित परिसर में किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला लाहौल-स्पिति के लगभग 20 लोग जो सीमान्त (fringe) तथा संरक्षित (protected) क्षेत्रों के आस-पास रहते हैं तथा हिमाचल प्रदेश वन विभाग के संरक्षित क्षेत्रों में तैनात अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी भाग लिया।

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला के निदेशक, डॉ. वी.पी. तिवारी ने मुख्य अतिथि, डॉ. आर. सी कंग, प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश, प्रशिक्षणार्थियों, संसाधन व्यक्तियों (Resource Persons) तथा अन्य उपस्थित लोगों का अभिन्दन तथा स्वागत किया। इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए, डॉ. तिवारी ने कहा कि वन और वन्य जीवों को सविधान समवर्ती सूचि में शामिल किया गया है। केन्द्रीय मंत्रालय वन-जीव संरक्षण सम्बन्धी नीतियों और नियोजन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश देने का कार्य करता है, जिसमें राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्यों के विकास के लिए वन्य जीव प्रभाग को सशक्त बनाने सम्बन्धी केन्द्रीय योजना तथा सहायता अनुदान देना इत्यादि शामिल है। राज्य सरकारें वन विभाग तथा वन्य जीव विभाग के माध्यम से इन संरक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष परियोजनाएं समय-समय पर चलाती रहती है, जिनका मुख्य उद्देश्य परिस्थिति तंत्र का संरक्षण तथा इसको सशक्त बनाना है। डॉ. तिवारी ने कहा कि संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले लोगों को कई प्रकार की प्रतिबंधों के कारण आम तौर पर भिन्न-भिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे उनकी आर्थिकी तथा आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ता है जिससे इन लोगों का जीवन प्रभावित होता है। इसी सोच के साथ संस्थान ने प्रयास किया कि इन लोगों को संरक्षित क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए तथा इन क्षेत्रों के संरक्षण के बारे में इन लोगों की भूमिका से अवगत करवाया जाए। हिमाचल प्रदेश में लाहौल-स्पिति तथा किन्नौर जिला का अधिकतर भू-भाग शीत-मरुस्थल जीव-मंडल के अंतर्गत आता है तथा इसमें जीवों और पौधों का अपना विशेष महत्त्व है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश वन्य जीव विंग के साथ मिलकर विशेष रूप से स्पिति क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के जीविका-अर्जन के वैकल्पिक स्रोतों को पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जोड़ते हुए तथा संरक्षण के दूरगामी लक्ष्य के मध्यनजर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की परिकल्पना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए हितधारकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ **डॉ. आर. सी. कंग, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य-जीव), हिमाचल प्रदेश** ने किया। प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए श्री कंग ने बताया कि **संरक्षित क्षेत्र /रक्षित क्षेत्र** किसी ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसकी उसके प्राकृतिक, पर्यावरणीय या सांस्कृतिक महत्व के कारण परिवर्तन या हानि से रक्षा की जा रही हो। रक्षित क्षेत्र भिन्न प्रकारों के होते हैं और उन्हें अलग-अलग स्तरों का संरक्षण दिया जा रहा है। संरक्षित क्षेत्र 'एक स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जो प्रकृति और उस से सम्बंधित पर्यावरणीय सेवाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए मान्य, समर्पित और व्यवस्थित हो'। आमतौर पर इन क्षेत्रों में मानव व्यवसायों और प्राकृतिक साधनों के उपयोग पर सीमाएं लगी होती है या पूर्ण पाबंदी होती है। इसलिए वन्य-जीव विंग, हिमाचल प्रदेश ने यह निर्णय लिया कि हिमालयन वन अनुसन्धान संस्थान, शिमला के साथ मिलकर इस महत्वपूर्ण विषय पर स्पिति घाटी के संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास इन संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षणार्थी इस प्रशिक्षण से अवश्य ही लाभान्वित होंगे तथा कहीं-न-कहीं हिमाचल प्रदेश वन विभाग को भी इन संरक्षित क्षेत्रों को संजोये रखने में सहायता मिलेगी।

इस अवसर पर अनपे विचार प्रकट करते **संस्थान के समूह समन्वयक (शोध) तथा पाठ्यक्रम समन्वयक, डॉ. कुलराज सिंह कपूर** ने बताया कि मनुष्य के लिये वन प्रकृति का ऐसा वरदान है, जिस पर उसका अस्तित्व, उन्नति एवं समृद्धि निर्भर है। वनों में जीवन बसर करने वाले वन्य जीवों से मानव जाति का सदियों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है परन्तु कालांतर में बुद्धि विकास के परिणामस्वरूप मनुष्य धीरे-धीरे वन्य जीवों से पृथक होता जा रहा है तथा अपने उदभव की कहानी को भुलाकर प्रकृति का स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है, जिससे प्राकृतिक असंतुलन बढ़ रहा है तथा मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है, इसलिए समय की पुरजोर मांग है कि मानवजाति प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर केवल सतत: विकास की संकल्पना पर कार्य करे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए डॉ. कपूर ने बताया कि इस प्रशिक्षण के दौरान पारिस्थिकी के विभिन्न पहलुओं तथा उनका जीविका उपार्जन की क्षमता, सांस्कृतिक पहलुओं तथा सामाजिक आर्थिक आयामों पर विभिन्न विषय-विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागि को जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा इसके साथ प्रायोगिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक दिन का क्षेत्रीय भ्रमण हेतु डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्विद्यालय, नौनी, सोलन का दौरा भी करवाया गया, जिसके दौरान विश्विद्यालय के विषय-विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का मार्ग दर्शन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता डॉ. सुनील चौधरी, भा.प्र.से., सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि उन्होने जनजातीय जिलों, लाहौल-स्पिति, किन्नौर तथा चंबा में विभिन्न पदों पर कार्य किया है तथा वहां की विषम परिस्थितियों से भली-भांति परिचित है। वहां के लोग बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना गुजर-बसर करते हैं तथा वहां कार्य-समय बहुत ही कम होता है क्योंकि अधिकतर समय वहां बर्फ जमी रहती है। उन्होंने बताया कि हिमाचल सरकार तथा केंद्र सरकार की सहायता से बहुत सी परियोजनाएं इन क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं परन्तु फिर भी यहाँ के निवासियों को निर्वहन के लिए कठिन प्रयास तथा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्रशिक्षण पर प्रकाश डालते उन्होंने कहा कि ईको-टूरिज्म की इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के स्थानीय युवाओं को इस क्षेत्र में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्हें वहां यात्रियों को होम-स्टे की सुविधा प्रदान करवानी चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की होम-स्टे में बेहतर सुविधाएँ तथा सेवाएं प्रदान करें ताकि सैलानी यहाँ से अच्छा अनुभव ले कर जाएं तथा दूसरे सैलानियों को भी इन क्षेत्रों के भ्रमण हेतु प्रेरित करें। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से आग्रह किया कि सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में चलाई जा रही विकासात्मक गतिविधियों में महिलाओं की भागेदारी भी सुनिश्चित करें। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों की संस्कृति के साथ-साथ हमें वहां की पारिस्थिति का भी संरक्षण सुनिश्चित करना है इसलिए वहां पाए जाने वाली वनस्पति तथा जीवों (flora & fauna) का संरक्षण भी सुनिश्चित करना होगा। डॉ. चौधरी ने सीधे संपर्क के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा इस बारे में उनकी राय भी ली। प्रशिक्षणार्थियों ने आयोजकों की प्रशंसा करते हुए बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्तमान समय की मांग है तथा प्रशिक्षण के दौरान सीमान्त समुदायों द्वारा अभ्यारण्यों का प्रबंधन में सहायता, ईको-टूरिज्म, शीत मरुस्थलों में साहसिक पर्यटन, वनस्पति एवं जीव प्रबंधन, बदलते परिपेक्ष्य में काबाइली क्षेत्रों में बागवानी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय, इत्यादि विषयों पर विषय-विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई जिससे उन्होंने लाभ होगा तथा अपनी आर्थिकी में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

अंत में उन्होंने हिमालयन वन अनुसन्धान संस्थान, शिमला तथा हिमाचल प्रदेश वन विभाग को इस महत्वपूर्ण विषय पर जिला लाहौल-स्पिति के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए बधाई दी तथा आशा व्यक्त की कि इस प्रशिक्षण से प्रतिभागी जो कुछ भी सीखेंगे यदि उसका कुछ भाग भी व्यावहारिक उपयोग में लायेंगे तो उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी तथा आर्थिकी में अवश्य ही सुधार होगा।

कार्यक्रम के अंत में डॉ. राज कुमार वर्मा, वैज्ञानिक ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा बताया कि इस प्रशिक्षण के दौरान अपने-अपने क्षेत्र में महारत रखने वाले संसाधन व्यक्ति/विषय विशेषज्ञ, जिनमें मुख्य रूप से डॉ. सुशील कापटा, मुख्य अन्वपाल (वन्य-जीव), डॉ.

जी.आर. साहिबी, अतिरिक्त प्रधान मुख्य-अरण्यपाल (ईको-टूरिज्म), डॉ. कुनाल अन्ग्रीश, वन-मंडल अधिकारी (वन्य-जीव), श्री प्रेम कुमार महंत, अध्यक्ष, श्री अनिरुद्ध चौहान, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान, मनाली तथा संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने प्रशिक्षण से सम्बंधित विभिन्न विषयों पर अपने व्याख्यान दिए तथा प्रशिक्षणार्थियों का मार्गदर्शन किया ।

ASAP

SOME GLIMPSES OF THE TRAINING PROGRAMME [Inaugural Day: 20.11.2017]



**A VISIT TO THE UNIVERSITY OF HORTICULTURE & FORESTRY
NAUNI, SOLAN [HIMACHAL PRADESH]
[21.11.2017]**



HIGHLIGHTS OF THE CONCLUDING DAY

[22.11.2017]



MEDIA COVERAGE OF THE TRAINING PROGRAMME

[20 November to 22 November, 2017]

प्रशिक्षण

लाहौल स्पीति और किन्नौर क्षेत्र के लोगों को एचएफआरआई के वैज्ञानिक दे रहे प्रशिक्षण

संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले सीमांत समुदायों के लोगों को जीवों और पौधों के विशेष महत्त्व समझा रहा एचएफआरआई

सिटी रिपोर्टर | शिमला

संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले सीमांत समुदायों के लोगों को संरक्षित वन प्राणियों और पौधों के बारे में अवगत करवाने की दिशा में एचएफआरआई की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लाहौल-स्पीति और किन्नौर के 20 लोगों को और वन विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला, डॉ.वीपी तिवारी ने कहा कि वन और वन्य जीवों को संविधान समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। राज्य सरकारें वन विभाग तथा वन्य जीव विभाग



सीमांत समुदायों के लोगों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एचएफआरआई के विशेषज्ञ।

के माध्यम से इन संरक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष परियोजनाएं समय-समय पर चलाती रहती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य परिस्थिति तंत्र का संरक्षण तथा इस्को सशक्त

बनाना है। डॉ. तिवारी ने कहा कि संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले लोगों को कई प्रकार की प्रतिबंधों के कारण आम तौर पर भिन्न-भिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता

जीविका उपाजन के बारे में भी दी जाएगी जानकारी

इस अवसर पर संस्थान के समूह समन्वयक (शोध) तथा पाठ्यक्रम समन्वयक, डॉ. कुलरज सिंह कपूर ने कहा कि इस प्रशिक्षण के दौरान परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं तथा उनका जीविका उपाजन की क्षमता, संस्कृतिक पहलुओं तथा सामाजिक आर्थिक आयामों पर विभिन्न विषय-विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ प्रयोगिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक दिन का क्षेत्रीय भ्रमण हेतु डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वनिकी विश्वविद्यालय, नौगाँ, सोलन का दौरा भी करवाया जाएगा, जिसके दौरान विश्वविद्यालय के विषय-विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का मार्ग दर्शन किया जाएगा।

है जिससे उनकी आर्थिकी तथा आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ता है जिससे इन लोगों का जीवन प्रभावित होता है। शुभारंभ के मौके पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्यजीव डा

आरसी कंग ने कहा कि आजीविका विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थी इस प्रशिक्षण से अवश्य ही लाभान्वित होंगे।

जनजातीय क्षेत्रों में वन्य जीवों को बचाने पर मंथन

वन अनुसंधान संस्थान शिमला में लगाई तीन दिवसीय कार्यशाला

हिमाचल दस्तक ब्यूरो।
शिमला

प्रदेश के जनजातीय जिलों में वन्य प्राणियों को बचाने के लिए शिमला स्थित वन अनुसंधान संस्थान में तीन दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला में जिला किन्नौर, लाहौल-स्पीति और पांगी के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सोमवार को कार्यक्रम का आगाज करते हुए पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ डॉ. आरसी कांग ने कहा कि वन और वन्य जीवों

शीत मरुस्थल क्षेत्रों में वन्य प्राणियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य : कांग

को संविधान समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्रालय वन-जीव संरक्षण संबंधी नीतियों और नियोजन के संबंध में दिशा-निर्देश देने का कार्य करता है। इसमें राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के विकास के लिए वन्य जीव प्रभाग को सशक्त बनाने और सहायता अनुदान देना शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकारें वन विभाग व वन्य जीव विभाग के माध्यम से इन संरक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष परियोजनाएं समय-समय पर चलाती रहती हैं,

जिनका मुख्य उद्देश्य परिस्थिति तंत्र का संरक्षण और सशक्त बनाना है। डॉ. कांग ने कहा कि संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले लोगों को कई प्रकार की प्रतिबंधों के कारण आम तौर पर विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इससे उनकी आर्थिकी व आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ता है। कांग ने कहा कि लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिले का अधिकतर भू-भाग शीत मरुस्थल जीव मंडल के अंतर्गत आता है। इसमें जीवों और पौधों का अपना विशेष महत्त्व है। इसी

उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वन अनुसंधान संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश वन्य जीव विंग के साथ मिलकर विशेष रूप से स्पीति क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के जीविका अर्जन के वैकल्पिक स्रोतों को परिस्थितिकी तंत्र के साथ जोड़ते हुए और संरक्षण के दूरगामी लक्ष्य के मध्यनजर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की परिकल्पना की। उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों को अवगत करवाया कि शीत मरुस्थल क्षेत्रों में वन्य प्राणियों की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है।

कार्यशाला का आयोजन

शिमला, 20 नवम्बर (ब्यूरो) : हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले सीमांत समुदायों के लोगों के लिए आजीविका विकल्प के विकास की दिशा में एकीकृत दृष्टिकोण विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। वन विभाग के वन्य जीव विंग की वित्तीय सहायता से आयोजित इस कार्यशाला में लाहौल-स्पीति के सीमांत व संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले 20 प्रतिभागी और वन विभाग के संरक्षित क्षेत्रों में तैनात अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान के डा. वी.पी. तिवारी बतौर मुख्यातिथि उपस्थित रहे।

पंजाब केसरी
ई-पेपर

Tue, 21 November 2017

epaper.punjabkesari.in//c/2389335



होम स्टे को बनाएं कमाई का जरिया

शिमला में आजीविका विकास कार्यक्रम में पर्यटक बढ़ाने पर जोर

■ दिव्य हिमाचल ब्यूरो, शिमला

प्रदेश के जनजातीय जिलों में होम स्टे कमाई का बेहतरीन विकल्प है। ऐसे में उक्त क्षेत्रों के लोगों वहां आने वाले पर्यटकों के लिए होम-स्टे की सुविधा प्रदान करवानी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलें, ताकि सैलानी यहां से अच्छा अनुभव ले कर जाएं।

यह बात हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा 'संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले सीमांत समुदायों के लिए आजीविका विकल्प के विकास की दिशा में एकीकृत दृष्टिकोण' विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

में कही गई। इस दौरान ईको टूरिज्म और होम स्टे योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी बांटी गई। वन विभाग के वन्य-जीव विंग की वित्तीय सहायता से आयोजित कार्यक्रम में जिला लाहुल-स्पीति के लगभग 20 लोग, जो सीमांत तथा संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, के साथ प्रदेश वन विभाग के संरक्षित क्षेत्रों में तैनात अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता डा. सुनील चौधरी, सचिव (सामान्य प्रशासन) ने की। उन्होंने कहा कि जनजातीय जिलों लाहुल-स्पीति, किन्नौर और चंबा के लोग बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना गुजर-बसर करते हैं।

हिमाचल सरकार तथा केंद्र सरकार की सहायता से बहुत सी परियोजनाएं इन क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं, परंतु फिर भी यहां के निवासियों को निर्वहन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।

ईको-टूरिज्म की इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। यहां के स्थानीय युवाओं को इस क्षेत्र में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षणार्थियों से आग्रह किया कि सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में चलाई जा रही विकासात्मक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों की संस्कृति के साथ-साथ हमें वहां की पारिस्थिति का भी संरक्षण सुनिश्चित करना है।

दिव्य हिमाचल

दिव्य हिमाचल

Fri, 24 November 2017

epaper.divyahimachal.com//c/23961582



संरक्षित क्षेत्रों में आजीविका विकल्प

वन अनुसंधान संस्थान में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

■ दिव्य हिमाचल ब्यूरो, शिमला

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा 'संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले सीमांत समुदायों के लिए आजीविका विकल्प के विकास की दिशा में एकीकृत दृष्टिकोण' विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सोमवार को प्रधान मुख्य अरण्यपाल डा. आरसी कंग ने शुभारंभ किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला लाहुल-स्पीति के लगभग 20 लोग, जो सीमांत तथा संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहते हैं और वन विभाग के संरक्षित क्षेत्रों में तैनात अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन 22 नवंबर को होगा। इस अवसर पर मौजूद मुख्यातिथि डा.



आरसी कंग ने कहा कि संरक्षित क्षेत्रों के आसपास संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला से डा. तिवारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय वन-जीव संरक्षण संबंधी नीतियों और नियोजन के संबंध में दिशा-निर्देश देने का कार्य करता है। वहीं संस्थान के समूह समन्वयक तथा पाठ्यक्रम समन्वयक

डा. कुलराज सिंह कपूर ने बताया कि मनुष्य के लिए वन प्रकृति का ऐसा वरदान है, जिस पर उसका अस्तित्व, उन्नति एवं समृद्धि निर्भर है। वहीं प्रायोगिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक दिन के क्षेत्रीय भ्रमण के लिए डा. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौपी का दौरा भी करवाया जाएगा, जिसके दौरान विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का मार्गदर्शन किया जाएगा।

दिव्य हिमाचल

दिव्य हिमाचल

Tue, 21 November 2017

epaper.divyahimachal.com//c/23893303



पर्यटकों को होम स्टे में दें अच्छी सुविधाएं मेहमाननवाजी ऐसी हो कि बार-बार आएंगे

एचएफआरआई में
रोजगार के क्षेत्रों के बारे में
दी जानकारी

सिटी रिपोर्टर | शिमला

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान में "संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले सीमांत समुदायों के लिए आजीविका विकल्प को लेकर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में रोजगार के अवसरों को लेकर जानकारी दी गई। एचएफआरआई में सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और फरिस्ट विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्य-जीव विंग की ओर से आयोजित



संरक्षित क्षेत्रों में रखे वाले लोगों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद सेक्रेटरी सामान्य प्रशासन डॉ. सुनिल चौधरी और अन्य अधिकारी।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन सेक्रेटरी सामान्य प्रशासन डा. सुनील चौधरी ने कहा कि लाहौल-स्पीति, किन्नौर तथा चंबा में लोग बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना

गुजर-बसर करते हैं तथा वहां कार्य-समय बहुत ही कम होता है क्योंकि अधिकतर समय वहां बर्फ जमी रहती है। उन्होंने बताया कि हिमाचल सरकार तथा केंद्र सरकार की सहायता

से बहुत सी परियोजनाएं इन क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं, परंतु फिर भी यहां के निवासियों को निर्वहन के लिए कठिन प्रयास तथा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्रशिक्षण पर प्रकाश डालते उन्होंने कहा कि ईको-टूरिज्म की इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। यहां के स्थानीय युवाओं को इस क्षेत्र में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्हें वहां यात्रियों को होम-स्टे की सुविधा प्रदान करवानी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की होम-स्टे में बेहतर सुविधाएं तथा सेवाएं प्रदान करें ताकि सैलानी यहां से अच्छा अनुभव ले कर जाएं तथा दूसरे सैलानियों को भी इन क्षेत्रों के भ्रमण हेतु प्रेरित करें।

प्रदेश में ईको-टूरिज्म की इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं : चौधरी

3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

शिमला, 23 नवम्बर (ब्यूरो): हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले सीमांत समुदायों के लिए आजीविका विकल्प के विकास को दिशा में एकीकृत दृष्टिकोण विषय पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश डा. सुनील चौधरी ने कहा कि प्रदेश में ईको-टूरिज्म की इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। यहां के स्थानीय युवाओं को इस क्षेत्र में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्हें वहां यात्रियों को होम-स्टे की सुविधा प्रदान करवानी चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की होम-स्टे में बेहतर सुविधाएं तथा सेवाएं प्रदान करें ताकि सैलानी यहां से अच्छा अनुभव लेकर जाएं तथा दूसरे सैलानियों को भी इन क्षेत्रों के भ्रमण के लिए प्रेरित करें। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्य-जीव विंग की वित्तीय सहायता से शिमला में आयोजित



शिमला : हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारी।

हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला लाहौल-स्पीति के करीब 20 लोगों जाकि सीमान्त तथा संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तथा हिमाचल प्रदेश वन विभाग के संरक्षित क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों ने भाग लिया।

समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए डा. सुनील चौधरी ने कहा कि उन्होंने वनवासीय जिलों लाहौल-स्पीति, किन्नौर तथा चंबा में विभिन्न पदों पर कार्य किया है तथा वहां की विषय परिस्थितियों से वह धलीभात पारंगत

हैं। वहां के लोग बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना गुजर-बसर करते हैं तथा वहां कार्य-समय बहुत ही कम होता है क्योंकि अधिकतर समय वहां बर्फ जमी रहती है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार तथा केंद्र सरकार की सहायता से बहुत सी परियोजनाएं इन क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं परंतु फिर भी यहां के निवासियों को निर्वहन के लिए कठिन प्रयास तथा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।

महिलाओं की भागेदारी भी सुनिश्चित करें

डा. सुनील चौधरी ने प्रशिक्षणार्थियों से अप्रहण किया कि सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में चलाई जा रही विकासक गतिविधियों में महिलाओं की भागेदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों की संस्कृति के साथ-साथ हमें वहां की परिस्थिति का भी संरक्षण सुनिश्चित करना है इसलिए क्या पाए जाने वाली वनस्पति तथा जीवों का संरक्षण भी सुनिश्चित करना होगा। इस मौके पर डा. चौधरी ने प्रशिक्षणार्थियों से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपयोगिता बारे जानकारी प्राप्त की तथा इस बारे उनकी राय भी ली। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों ने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्तमान समय की मांग है तथा प्रशिक्षण के दौरान सीमान्त समुदायों द्वारा अत्याचारों का प्रबंधन में सहायता, ईको टूरिज्म, शीत मरुस्थलों में साहसिक एडवेंचर, कनस्प्रीट एंड जीव प्रबंधन, बदलते परिपेक्ष में कबचली क्षेत्रों में बगवानी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय आदि विषयों पर विविध विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई जिससे उन्होंने लाभ हासिल तथा अपनी आर्थिकी में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान में जनजातीय क्षेत्रों में वन्य प्राणी बचाने पर मंथन

जनजातीय जिलों में ईको टूरिज्म की अपार संभावनाएं : सुनील

◆ तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में दी कई महत्वपूर्ण जानकारी

हिमाचल दरतक ब्यूरो | शिमला

प्रदेश के जनजातीय जिलों में वन्य प्राणी को बचाने के लिए हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला में तीन दिन तक मंथन किया गया। इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान लाहौल-स्पीति, किन्नौर और पांगी के करीब 20 लोगों ने भाग लिया।

शिविर का सम्पन्न एसएडों के सचिव डा. सुनील चौधरी ने किया। इस दौरान चौधरी ने कहा कि हिमाचल व केंद्र सरकार की



शिमला : तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन पर प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया।

सहायता से बहुत सी परियोजनाएं जनजातीय क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं, लेकिन यहां के निवासियों को

निर्वहन के लिए कठिन प्रयास और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में वन्य

प्राणियों को बचाने के लिए हमें सहयोग करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ईको टूरिज्म की इन

क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। यहां के स्थानीय युवाओं को इस क्षेत्र में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्हें वहां यात्रियों को होम-स्टे की सुविधा प्रदान करवानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की होम-स्टे में बेहतर सुविधाएं व सेवाएं प्रदान करें, ताकि सैलानी यहां से अच्छा अनुभव ले कर जाएं और दूसरे सैलानियों को भी इन क्षेत्रों के भ्रमण हेतु प्रेरित करें। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से अप्रहण किया कि सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में चलाई जा रही विकासक गतिविधियों में महिलाओं की भागेदारी भी सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया।